रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारी

बनाम

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

24 अक्टूबर, 1989

[न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत और न्यायमूर्ति के. रामास्वामी]

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985: एसएस। 4 और 10 - रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड-पुनर्वास-के लिए निर्देश।

प्रतिवादी-कंपनी के स्वामित्व वाली चार बड़ी औद्योगिक इकाइयों को 9 सितंबर, 1984 से बंद कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10,000 कर्मचारी रोजगार से वंचित हो गए थे। रिट याचिका में, श्रमिकों ने बंद होने के बाद की अवधि के लिए वेतन और मजदूरी का तत्काल भुगतान और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1984 में संशोधन के अनुसार मुआवजा और भविष्य निधि खाते, ग्रेच्युटी आदि के तहत बकाया का भुगतान करने की मांग की। इस बीच उच्च न्यायालय ने 22 मई, 1986 को कंपनी अधिनियम के तहत एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया था।

इस अदालत ने 29 अक्टूबर, 1987 को केंद्र सरकार को बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 4 के संदर्भ में गठित बोर्ड को एक संदर्भ देने का निर्देश दिया था, जो कि धारा 10 के तहत विचार के अनुसार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक योजना तैयार करने के लिए लागू हुआ था और इसे चार महीने के भीतर न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत करें। 7 सितंबर, 1988 को, अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बिहार राज्य कंपनी के राष्ट्रीयकरण के लिए इच्छुक था और राष्ट्रीयकरण के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए अध्यक्ष के रूप में भारतीय संघ के उद्योग सचिव को लेकर एक समिति तुरंत गठित करने का निर्देश दिया। 13 दिसंबर, 1988 को अदालत ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि कागज और बोर्ड इकाई को छोड़कर तीन इकाइयां व्यवहार्य थीं और उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता था, और पक्षों को व्यवहार्य इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने का अवसर देने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। 8 अगस्त, 1989 तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। इसके बाद बिहार राज्य और भारत संघ ने अलग-अलग अपने बयान दायर किए और महान्यायवादी द्वारा तैयार ज्ञापन भी न्यायालय को उपलब्ध कराया गया।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित:

1. राष्ट्रीय क्षति के अलावा लगभग 10000 परिवारों को पांच वर्षों से अधिक समय से आजीविका से वंचित कर दिया गया है और श्रमिकों को गंभीर खतरे में डाल दिया गया है। उनके मजदूरी की एक बड़ी राशि बकाया है। कई वित्तीय संस्थानों को कंपनी से बड़े पैमाने पर बकाया वसूलना है। ऋणपत्र न्यास के न्यासियों ने भी अपने दावे को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इनके अलावा, कंपनी के मालिकों ने यह भी अनुरोध किया है कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से कंपनी की संपत्तियों को छीनने की स्थिति में वे मुआवजे के हकदार हैं। बहुत सी परिसंपत्तियाँ तेजी से बेकार हो रही हैं और जल्द ही कबाड़ बन जाएंगी। यदि कंपनी का परिसमापन हो जाता है, तो देनदारियां परिसंपत्तियों से कहीं अधिक हो जाएंगी और परिसंपत्तियों पर पहले या दूसरे प्रभार के बावजूद, लेनदारों को उल्लेखनीय लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए यह सर्वोपरि महत्व है कि व्यवहार्य इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और उत्पादन में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। [620 डी, ए-सी]

2.1 बिहार राज्य को पुनर्वास प्रशासक के रूप में एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है। [620 एच]

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अनंतिम परिसमापक उस कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को प्रशासक को सौंप देगा, जिन्हें उसने उस न्यायालय के आदेश के तहत अपने हाथ में ले लिया था। कंपनी की जिन

परिसंपत्तियों का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है, वे तुरंत प्रशासक के पास निहित हो जाएंगी। [621 ए]

2.3 वित्तीय और अन्य संस्थानों से जुड़ी कंपनी की परिसंपत्तियां एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यवाही के लिए उपलब्ध नहीं होंगी, और इसके बाद कंपनी के खिलाफ की गई और लंबित या उठाए जाने वाली कार्यवाही के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए रोक होगी, और इस अवधि के लिए परिसीमा निलंबित रहेगी (621 डी-ई)

2.4 बिहार की राज्य सरकार आठ सप्ताह के भीतर अधिग्रहीत की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत के बदले 15 करोड़ रुपये की राशि प्रशासक के पास जमा करेगी। भारत संघ द्वारा योजनागत सहायता से राज्य को 15 करोड़ रुपये की समान राशि प्रदान की जाएगी। राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि का उपयोग, श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान और वित्तीय संस्थानों और अन्य पार्टियों के सुरक्षित ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की गई थी। प्रशासक डालमिया नगर में संचालित राज्य के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता खोलेगा जिसमें दो धनराशियां जमा की जाएगी (621 एफ-एच]

2.5 प्रशासक कंपनी के मालिकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य पक्षों के दावों की छह महीने के भीतर जांच करने के लिए और दिशानिर्देश

के लिए मामले को वापस न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और एक लेखा अधिकारी के साथ एक समिति का गठन करेगा। [622 ए]

2.6 सभी वस्तुओं की एक सूची चार सप्ताह के भीतर बनाई जाएगी। चार सप्ताह के भीतर एक नई कंपनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तकनीकी सलाहकारों और अन्य सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति दो महीने के भीतर की जाएगी। छंटनी किये गये कर्मचारी चरणों में काम पर वापस आ जाएंगे। तीन इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुन: सक्रिय किए जाने के बाद तीन महीने के भीतर पेपर इकाई की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पार्टियों को आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। [622 सी-डी एंड ई]

2.7 मामला लंबित रहेगा, जिसे 1 मार्च 1990 को फिर से बुलाया जाएगा। [622 एच]

मौलिक क्षेत्राधिकार: 1985 की रिट याचिका संख्या 5222

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

(1988 की रिट याचिका संख्या 443 और 754 के साथ)

याचिकाकर्ताओं के लिए आर के. गर्ग, एस. के. वर्मा, पी. अंशु मिश्रा और आर. एस. सिंह 1985 की रिट याचिका संख्या 5222 में।

याचिकाकर्ताओं के लिए जी. बी. पाई और एस. के. सिन्हा 1988 की रिट याचिका संख्या No.754 में।

प्रत्यर्थियों की लिए के. परासरन, महान्यायवादी, जी. रामास्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल सुश्री ए. सुभाषिनी, प्रोबीर मित्रा और के. स्वामी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

बिहार राज्य के रोहतास जिले के डालमियानगर में स्थित रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्रमिकों ने 8 जुलाई, 1985 को इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र भेजा जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की चार इकाइयाँ थीं, अर्थात् कागज और बोर्ड, सीमेंट, एस्बेस्टस और वनस्पति घी संयंत्र; प्रबंधन ने 9 सितंबर 1984 से उद्योगों को बंद कर दिया और लगभग 10,000 कर्मचारियों को रोजगार से वंचित कर दिया। यह प्रार्थना की गई कि कॉलोनी में बिजली की तत्काल बहाली की जाए, बंद होने के बाद की अवधि के लिए वेतन और मजदूरी का भुगतान किया जाए और औद्योगिक विवाद अधिनियम में 1984 के संशोधन के अनुसार मुआवजा दिया जाए और भविष्य निधि खाते उपदान के तहत बकाया आदि का भी भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। इस पत्र

को एक रिट याचिका के रूप में दर्ज किया गया और नोटिस जारी किया गया। इस बीच दिनांक 22.5.1986 के आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम के तहत एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया। इस न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में नियोक्ता, अनंतिम परिसमापक, बिहार राज्य और भारत संघ नियत समय पर उपस्थित हुए हैं।

न्यायालय ने 27.4.1987 को बकाया मजदूरी के मामले में परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा भुगतान करने का एक अंतरिम आदेश दिया। न्यायालय ने 22.7.1987 को इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कंपनी के पुनर्गठन का प्रस्ताव उसके सुझाव के अनुसार चल रहा था और कहा कि वित्तीय संस्थानों के दावों पर बाद में विचार किया जाएगा। 28 अक्टूबर, 1987 को न्यायालय ने कहाः

"इस न्यायालय ने भारत संघ और विद्वान अटॉर्नी जनरल को यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्या उस कंपनी को पुनर्जीवित करना संभव है जो अचानक बीमार हो गई है। विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि इस बीच रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, जिसे 8 जनवरी, 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, लागू हो गया है और अब इसकी धारा 4 के संदर्भ में एक बोर्ड का गठन किया गया है। उनका सुझाव है कि उस बोर्ड को संदर्भ दिया जा सकता है

और बोर्ड को कंपनी के पुनरुद्धार के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत योजना तैयार करने के लिए बुलाया जा सकता है और योजना को अधिनियम के तहत आगे से निपटने की अनुमति देने के बजाय, बोर्ड को इस न्यायालय के विचारार्थ योजना के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। ऊनका यह भी कहना है कि मामले के विशेष तथ्यों में योजना को वैधानिक अपील के अधीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील इस बात से सहमत हैं कि विद्वान अटॉर्नी जनरल के सुझाव के अनुसार प्रयास किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को निर्देश दिया और बोर्ड को योजना तैयार करने के लिए चार महीने का समय दिया गया। इस अदालत ने 7.9.1988 को इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बिहार राज्य कंपनी के राष्ट्रीयकरण के लिए इच्छुक था। भारत संघ ने एक हलफनामा दायर किया कि यदि राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसका समर्थन किया जाएगा। इस न्यायालय ने 7.9.1988 के इस आदेश में कहाः

"इस पृष्ठभूमि में मामले की जांच करने पर हमारा मानना है कि यह सभी के हित में है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान को पुनर्जीवित किया जाए और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा। इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीयकरण के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए तुरंत

भारतीय संघ के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। समिति में सचिव, उद्योग, बिहार सरकार, ऋणदाता वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, भारत सरकार के वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। समिति को मामले की जांच करनी चाहिए और छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए..........।"

कोर्ट ने 9.8.1989 को यह कहकर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया:

"इस अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पेपर यूनिट को छोड़कर तीन इकाइयां व्यवहार्य हैं और उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस अदालत ने 13 दिसंबर, 1988 को रिपोर्ट पर विचार किया और तीन व्यवहार्य इकाइयों के पुनरुद्धार के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए पक्षों को अवसर देने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। जैसा कि हम पाते हैं, कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। स्थगित तिथि तक तौर-तरीकों पर चर्चा की जानी चाहिए और अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और अदालत को सूचित किया जाना चाहिए ताकि तीन इकाइयों को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जा सके।

रिपोर्ट ने संकेत दिया कि पेपर इकाई के संबंध में समिति की राय नहीं थी कि यह व्यवहार्य थी। विद्वान महान्यायवादी और श्री पाई से अदालत ने पेपर इकाई के पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने का

अनुरोध किया था। विद्वान महान्यायवादी की ओर से सुश्री सुभाषिनी ने कहा कि दो सप्ताह का समय दिए जाने पर आगे की चर्चा की जाएगी और पेपर इकाई के संबंध में पूर्ण निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।"

भारत संघ और बिहार राज्य द्वारा 12.9.1989 को एक संयुक्त ज्ञापन दायर किया गया था जिसे न्यायालय ने इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया कि ज्ञापन में पुनरुद्धार के संबंध में कोई स्पष्ट और निश्चित संकेत नहीं था। इसके बाद, बिहार राज्य और भारत संघ ने अलग-अलग अपने बयान दर्ज किए हैं और विद्वान महान्यायवादी द्वारा तैयार और वितरित ज्ञापन की एक प्रति भी हमारे समक्ष दायर की गई है। हमने मामले में पक्षों के विद्वान वकीलों को भी सुना है।

यह विवादित नहीं है कि मजदूरी की एक बड़ी राशि बकाया है। कई वित्तीय संस्थानों को कंपनी से बड़े पैमाने पर बकाया वसूलना है। ऋणपत्र न्यास विलेख के न्यासियों ने भी अपने दावे को बनाए रखने के लिए इस अदालत में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इनके अलावा, कंपनी के मालिकों ने यह भी अनुरोध किया है कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से कंपनी की संपत्तियों को छीनने की स्थिति में वे मुआवजे के हकदार हैं।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कंपनी अब पांच साल से अधिक समय से बंद है। बहुत सारी परिसंपत्तियाँ तेजी से बेकार हो रही हैं और जल्द ही कबाड़ बन जाएंगी। आधिकारिक परिसमापक द्वारा रखे

गए कुछ स्टॉक का निपटान करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी न किसी कारण से बिक्री को पूरा करना संभव नहीं हो सका है और हालांकि इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बिक्री आय का उपयोग बकाया-मजदूरी के भुगतान के लिए किया जाएगा, जो संभव नहीं हो पाया है। कंपनी के खिलाफ दावे किए गए हैं और शायद निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कंपनी को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है और उसका परिसमापन हो जाता है, तो देनदारियां परिसंपत्तियों से कहीं अधिक हो जाएंगी और परिसंपत्तियों पर पहले या दूसरे प्रभार के बावजूद, लेनदारों को उल्लेखनीय लाभ नहीं हो सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लगभग 10,000 परिवारों को पांच साल से अधिक समय से रोजगार से वंचित कर दिया गया था और राष्ट्रीय क्षति के अलावा, श्रमिकों को गंभीर खतरे में डाल दिया गया है। इन परिस्थितियों में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार्य इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुनर्जीवित किया जाए और उत्पादन में आने की अनुमति दी जाए। जब तक कंपनी की देनदारियों के संबंध में उचित समय के लिए रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक तीन इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रयास लेनदारों के हस्तक्षेप पर हतोत्साहित होना तय है, जबकि एक बार कंपनी को पुनर्जीवित करने और बड़ी वाणिज्यिक गतिविधियों को जारी रखने के बाद, लाभ अर्जित करना तय है और एक कर्तव्यनिष्ठ और विवेकपूर्ण प्रशासन निश्चित रूप से,

उचित समय पर, ऋणों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगा। फिलहाल सवाल प्राथमिकताओं का है। यह समझदारी से तय करना होगा कि किसे आगे जाने दिया जाए और किसे इंतजार कराया जाए।

इस पृष्ठभूमि में और बिहार राज्य और भारत संघ द्वारा दायर ज्ञापनों के आधार पर और विद्वान महान्यायवादी द्वारा तैयार किए गए और महान्यायवादी की सहमति से दूसरे पक्ष के लिए श्री पाई द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए नोट के आधार पर, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैंः

1. बिहार राज्य पुनर्वास प्रशासक के रूप में उचित व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ आई. ए. एस. संवर्ग से एक अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

2. पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पेशेवर परिसमापक कंपनी की सभी संपत्तियों को प्रशासक को सौंप देगा, जिसे उसने अदालत के आदेश के तहत अपने कब्जे में ले लिया है। कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनका अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है। कंपनी की ऐसी संपत्तियां जिन्हें अभी तक अनंतिम परिसमापक द्वारा अपने कब्जे में नहीं लिया गया है, उचित अधिकारी नामित होने पर तुरंत उसे सौंप दी जाएंगी और हमारे वर्तमान आदेशों के तहत उसे कंपनी की ऐसी संपत्तियां कब्जे में लेने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाएगी।. प्रशासक के इस निर्णय कि संपत्ति कंपनी की है और प्रशासक

द्वारा इसे अपने कब्जे में ले लिया जाएगा से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक अपील विचारणीय होगी और ऐसी खंडपीठ का गठन करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों को नामित किया जाएगा। सुविधा के लिए एक उचित अवधि के लिए वही न्यायाधीश नामांकित पीठ पर बने रहेंगे।

3. वित्तीय और अन्य संस्थानों से भारग्रस्त कंपनी की परिसंपत्तियाँ आज से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यवाही के लिए उपलब्ध नहीं होगी, और इसके बाद कंपनी के खिलाफ की गई और लंबित या की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए रोक होगी, और आज के हमारे आदेशों के तहत इस अवधि के लिए परिसीमन निलंबित रहेगा। अनुरोध किए जाने पर अदालत स्थगन की अवधि बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी।

4. बुक वैल्यू के अनुसार बिहार राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली पूरी संपत्ति की लागत और कंपनी के खिलाफ बकाया राशि 15 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर होने का अनुमान है। बिहार राज्य सरकार ने हमारे सामने आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रशासक के साथ 15 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का वादा किया है। भारत संघ द्वारा राज्य के लिए योजनागत सहायता से बिहार राज्य को 15 करोड़ रुपये की समान राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भुगतान की

गई 15 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग, उचित समय पर, श्रमिकों को बकाया मजदूरी के भुगतान और वित्तीय संस्थानों और अन्य पार्टियों के सुरक्षित ऋणों के वितरण के लिए किया जाएगा, जिनके लिए कंपनी की की परिसंपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की गई थी। प्रशासक डालमियानगर में संचालित बिहार राज्य के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता खोलेगा जिसमें 15-15 करोड़ रुपये की दो धनराशि जमा की जाएगी।

5. प्रशासक कंपनी के मालिकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य पक्षों के दावों की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और राज्य सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में कम से कम पांच साल के अनुभव वाले एक लेखा अधिकारी की एक समिति गठित करेगा। यह अब से छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। एक बार जब लेनदारों की सूची सभी उचित विवरणों के साथ तय हो जाती है, तो मामले को निर्देशों के लिए इस अदालत को सूचित किया जाना चाहिए और यह अदालत अंततः उस आंकड़े को इंगित करने के लिए स्वतंत्र होगी जिस पर ऐसे प्रत्येक दावे का निपटारा किया जाएगा।

अब से चार सप्ताह के भीतर सभी वस्तुओं की एक सूची बनाई जाएगी।

अब से चार सप्ताह के भीतर एक नई कंपनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

तकनीकी सलाहकारों और अन्य सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति दो महीने के भीतर की जाएगी।

एस्बेस्टस, सीमेंट और वनस्पति संयंत्रों को आवश्यक मरम्मत के बाद चालू किया जाएगा।

हटाए गये कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से काम पर वापस आ जाएंगे। पहले चरण में एक हजार श्रमिकों को प्रवेश दिया जाएगा, दूसरे चरण में इतनी ही संख्या में श्रमिकों को प्रवेश दिया जाएगा और तीसरे चरण में, उद्योगों को व्यवहार्य तरीके से चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या को अंतिम रूप दिया जाएगा। रोजगार प्रदान करने के लिए यथासंभव सभी त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

तीन इकाइयों के संबंध में कंपनी के दोबारा चालू होने के तीन महीने के भीतर कागज इकाई की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पक्षकारों को आवश्यकता पड़ने पर आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। आदेश के वास्तविक उद्देश्य और भावना को ध्यान में रखते हुए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित लोगों द्वारा हर संभव

प्रयास किया जाना चाहिए। हम किसी के मन में संदेह नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हमारे आदेश का उद्देश्य कंपनी को पुनर्जीवित करना और इसे व्यवहार्य रूप से कार्यान्वित करना है। इसलिए, न्यायालय के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक व्यक्ति से इस तरह से काम करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह उस उद्देश्य को पूरा करे।

हम निर्देश देते हैं कि मामला इस न्यायालय में लंबित रहेगा और इस आदेश द्वारा निपटान किया नहीं माना जाएगा। मामले को 1 मार्च, 1990 को सुनवाई के लिए बुलाएं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।